अध्ययन सामग्री निर्माण
Dr. SHAKEEL HUSAIN
Head . Dept. of Political Science
Govt. VYT.PG Autonomous College
Durg CG.
shakeelvns27@gmail.com

ई गवर्नेंस का संस्थागत ढांचा **Structural framework of e-governance.**

NeGP नेशनल ईगवर्नेन्स प्लान NATIONAL E-GOVERNANCE PLAN

18 मई 2006 को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और 2011 में चार बड़े प्रोजेक्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक वितरण प्रणाली **PDS** तथा डाक विभाग में शुरू किए गए। e-governance को तेज गति देने के लिए **31** Mission mode projects मिशन मोड प्रोजेक्ट्स **MMP** विभिन्न विभागों में प्रारंभ किए गए तब से अब तक इगवर्नेंस की दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति हुई है और केंद्र से लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक इसका व्यापक संस्थागत ढांचा विकसित कर नेटवर्क तैयार किया गया है जिसमें प्रमुख हैं।

स्टेट डेटा सेंटर **SDCs**

प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक स्टेट डाटा सेंटर स्थापित किया गया है जो एकीकृत कमान के रूप में ई गवर्नेंस संबंधी परियोजनाओं का नियमन करता है। प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में तकनीकी सहयोग के लिए संस्थाएं निर्धारित है जिनके माध्यम से स्टेट डाटा सेंटर तकनीकी रूप से संचालित होता है।

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क **SWAN**

मार्च **2005** में **3334** करोड़ की लागत के साथ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित किया गया। यह नेटवर्क राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक 8 एमबीपीएस से लेकर 100 एमबीपीएस तक क्षमता के ईसर्विस केंद्र स्थापित करता है। स्टेट हेड क्वार्टर डिस्टिक हेड क्वार्टर्स ब्लॉक और तहसील स्तर पर एरिया नेटवर्क स्थापित होता है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

DR SHAKEEL HUSAIN

SWAN Three Tier Architecture

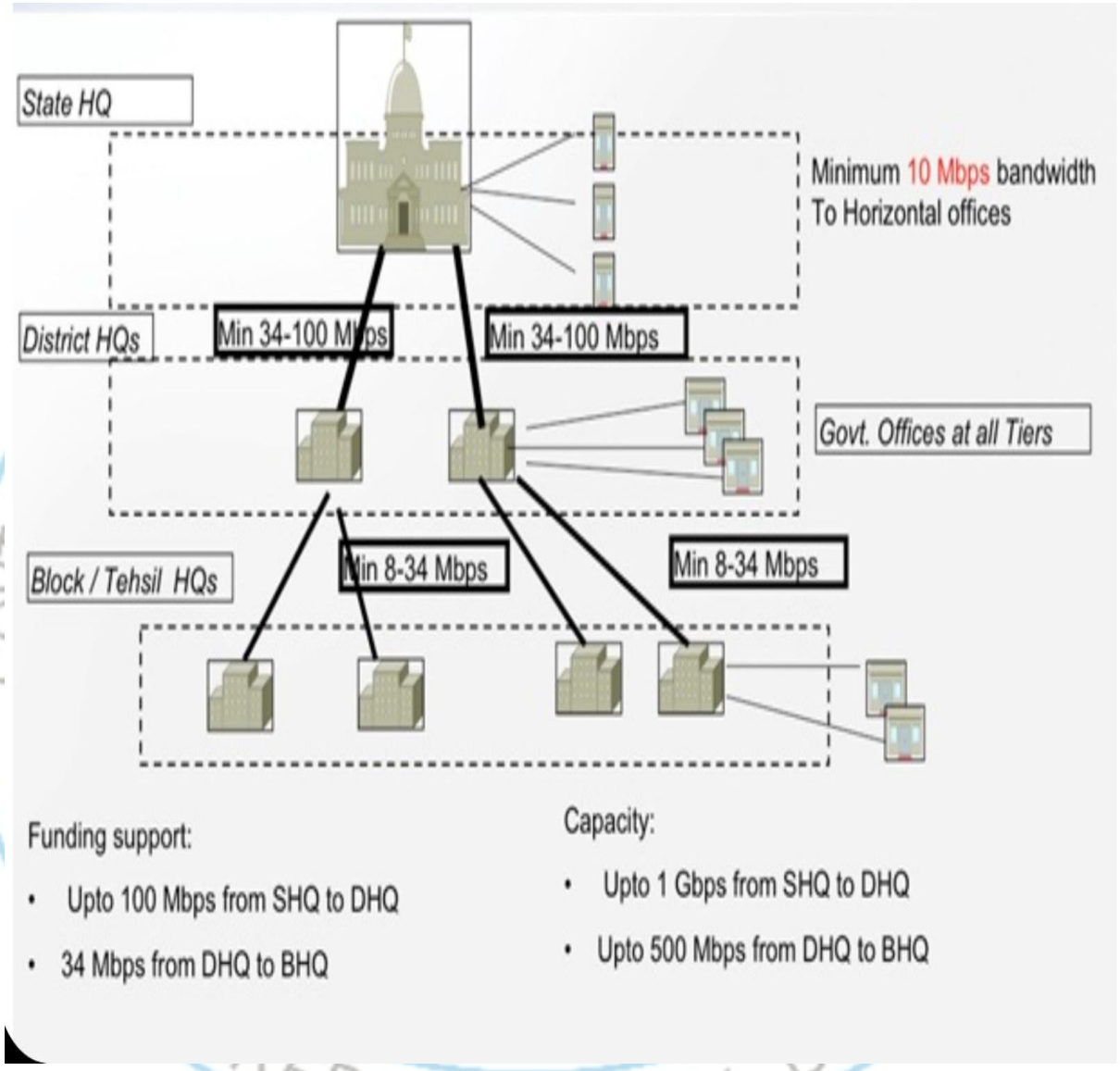

कॉमन सर्विस सेंटर **CSCs**

इस परियोजना में प्रत्येक 6 गांव के बीच एक कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस के लिए स्थापित करने और एक लाख गांव को कवर करने का लक्ष्य रखा गया। इसके दूसरे चरण में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ई-सर्विस से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अधिकांश सुविधाएं जैसे आधार, पैन कार्ड ,डिजिलॉकर ,पीडीएस ,ई- वाहन ,आयुष्मान भारत योजना, फसल बीमा योजना, उज्जवला योजना ,किसान सम्मान निधि योजना ,किसान क्रेडिट कार्ड योजना ,ई श्रम पंजीकरण सिबिल रजिस्ट्रेशन फास्ट टैग सर्विस डीजी पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग ,ई कोर्ट आदि भी कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना के तहत ही संचालित होते हैं यह सामान्यतः **G2C** सेवा के अंतर्गत आता है।

नेशनल **e-governance** डिलीवरी गेटवे **NSDG**

यह एक तकनीकी संरचना है जिसके माध्यम से भारत सरकार की सभी योजनाएं जनता तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरलता पूर्वक पहुंचाने के लिए स्थापित नेटवर्क्स में एकीकरण का कार्य किया जाता है । यह विभिन्न ई नेटवर्क के एकीकरण और परिचालन का कार्य देखता है ।

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे **SSDG**

राज्य स्तर पर सरकार की योजनाओं और सुविधाओं को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सफलतापूर्वक जनता तक पहुंचाने के लिए स्थापित नेटवर्क में एकीकरण हेतु स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे स्थापित किया गया है ।

मोबाइल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे **MSDG**

विभिन्न एप्स के द्वारा मोबाइल सर्विस प्रदान करने वाली सुविधाओं के एकीकरण हेतु उसकी स्थापना की गई है जैसे आईवीआर फोन तकनीकी द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग, डिजिलॉकर, एम आधार ,आदि ।

ई-प्रमाण **e-pramaan**

इसके माध्यम से ई ऑथेंटिकेशन का कार्य किया जाता है । **OTP** ऑथेंटिकेशन के द्वारा ई प्रमाणन किया जाता है । इसमें किसी भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन में साइन अप, साइन इन, तथा पासवर्ड प्रोटेक्शन ,आईडेंटिटी मैनेजमेंट और केवाईसी वेरीफिकेशन आदि **OTP** के द्वारा ई प्रमाणन का कार्य किया जाता है ।

G1 Cloud Meghraj

मेघराज परियोजना की स्थापना क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए की गई है । यह क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड सेवाएं प्रदान करने और उसका नियमन करने का कार्य करता है
स्थापना e-governance प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए की गई है ।

Mission mode projects मिशन मोड प्रोजेक्ट्स MMP

मिशन मोड प्रोजेक्ट किसी विशेष विभाग से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की परियोजना है जिसे मिशन मोड पर लागू किया गया है इसी से इसका महत्व स्थापित है वर्तमान समय में कुल **31** मिशन मोड पर योजनाएं स्वचालित हैं जिनमें **11** प्रोजेक्ट केंद्रीय प्रोजेक्ट हैं **13** प्रोजेक्ट राज्य स्तर के प्रोजेक्ट हैं और **7** प्रोजेक्ट एकीकृत प्रोजेक्ट हैं जिनका विवरण निम्नांकित रूप में है ।

Sr.	CENTRAL MMPs	STATE MMPs	INTEGRATED MMPs
1	Banking	Agriculture	CSC कामन सर्विस सेन्टर
2	Central excise and customs	Commercial tax	e-biz
3	Income tax (IT)	E-districts	e-courts
4	Insurance	Employment exchange	e-procurement
5	MCA21 कारपोरेट मंत्रालय	Land records NLRMP	EDI (e-trade)

DR. SHAKEEL HUSAIN

6	PASSPORT	e- municipalities	India portal
7	Immigration, Visa and foreigners registration & tracking.	Treasuries computerisation	National e-governance service delivery gateway
8	Pension	Police CCTNS	
9	e-office	Road transport	
10	Posts	PDS	
11	UID	Education	
12		Health	
13		e-panchayats	

GOVT. VYT. PG AUTONOMOUS COLLEGE DURG (C.G)
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः
LET THE NOBLE THOUGHTS COME FROM EVERYWHERE
ACCREDITED AS A+ BY NAAC
Dr. SHAKEEL HUSAIN